शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 6 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 02 – 09 फरवरी 2026 मूल्य पांच रूपये

आर्थिक संकट से सरकार की नीयत और नीति पर उठते सवाल

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार अपने ही बोझ तले दम तोड़ने के कगार पर पहुंच गयी है? यह सवाल इसलिये उठ खड़ा हुआ है कि 16वें वित्त आयोग ने सत्रह राज्यों को मिल रही राजस्व घाटा अनुदान योजना को बन्द कर दिया है। संविधान की धारा 275(1) के तहत केन्द्र की ओर से राज्यों को यह अनुदान मिल रहा था। जिन राज्यों की राजस्व आय उन राज्यों के राजस्व व्यय से कम हो जाती थी उन राज्यों को सहायता देने के लिये यह अनुदान दिया जाता था। लेकिन इस अनुदान की पात्रता और आकार का आकलन वित्त आयोग के जिम्मे था। वित्त आयोग का गठन महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसकी सिफारिशें सबको मान्य होती हैं। इसकी सिफारिशों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन सिफारिशों का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। राज्यों में वित्तीय अनुशासन गायब होता चला गया। इस वस्तु स्थिति को देखते हुये वर्ष 2003 में राज्यों में वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिये एफआरबीएम अधिनियम लाया गया। यह रखा गया कि राज्य अपने जीडीपी के तीन प्रतिशत तक ही कर्ज ले सकते हैं। प्रतिबद्ध राजस्व व्यय के लिये कर्ज लेने का कोई प्रावधान नहीं है। कर्ज केवल पूंजीगत परिसंपत्तियां खड़ी करने के लिये ही लिया जा सकता है ताकि उनसे राजस्व मिले। लेकिन इस अनुशासन का भी राज्यों पर ज्यादा असर नहीं हुआ। जबकि 2003 में एक उच्च राज्य स्तरीय बैठक वरिष्ठ अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में हुई थी और जो पद दो वर्षो से किन्हीं कारणों से खाली चले आ रहे थे उन्हें समाप्त करने का फैसला लिया गया था। इस फैसले पर उस समय भी भाजपा और कांग्रेस में सदन में विवाद हुआ था। लेकिन यह सब होने के बाद भी प्रदेश में वित्तीय अनुशासन नहीं आया। दशकों तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुये और पलान के पैसे से नॉन पलान के खर्चे चलाये गये। जो प्रदेश 1993 तक कर्ज मुक्त था आज उसका कर्ज एक लाख करोड़ से कैसे बढ़ गया? जो कर्ज जीडीपी के 3% तक रहना चाहिए था वह आज करीब 45% तक पहुंच गया है। जबकि एफआरबीएम अधिनियम लाकर इस कर्ज को शून्य पर लाने की कवायत की गई थी। लेकिन जब चुनावी लाभ लेने के लिये वायदों की रेवड़ियां बंटनी शुरू हुई तब वित्तीय अनुशासन लाने के लिये आज राजस्व घाटा अनुदान बन्द करने पर आना पड़ा है। 15वें वित्त आयोग की जब रिपोर्ट आयी थी तो उसी में यह दर्ज था कि यह राजस्व घाटा अनुदान 31 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएगा। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के घोड़े पर सवार सुक्खू सरकार इस सच्चाई को समझ नहीं पायी और आज हर तरह की प्रतिक्रियाएं देने के कगार पर पहुंच गयी है। पहली बार है कि प्रदेश के वित्त सचिव को अपनी प्रतिक्रिया देते हुये हर सुविधा पर कैंची चलाने की बात करनी पड़ी है। वित्त सचिव की प्रतिक्रिया आज हर जगह सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गयी है। वित्त सचिव ने बिजली बोर्ड प्राइवेट सैक्टर के हवाले करने की बात की है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में पिछले लम्बे समय से बोर्ड को निजी हाथों में सौंपने की चर्चाएं चली हुई हैं। परिवहन निगम को भी प्राइवेट हाथों में सौंपने की चर्चाएं हैं। पर्यटन निगम के होटलों को प्राइवेट क्षेत्र को देने की बात हो रही है। राजस्व घाटा अनुदान बन्द किये जाने को ऐसे दिखाया जा रहा है कि सरकार को सब कुछ निजी हाथों में सौंपना पड़ेगा। जबकि यह घाटा अनुदान बन्द करने के साथ ही वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं और आपदा प्रबंधन के लिये उदार रूप से धन का प्रावधान किया है। लेकिन इस पैसे को दूसरे राजस्व व्यय वेतन, पैन्शन और ब्याज की अदायगी पर खर्च नहीं किया जा सकेगा। आज सरकार को यह सार्वजनिक करना पड़ेगा कि उसकी कौन सी जन कल्याण की योजनाएं प्रभावित होने जा रही हैं। अब उसकी हर योजनाओं को आम आदमी की आवश्यकता के तराजू में तोल कर देखा जायेगा। प्रदेश में एक लाख करोड़ से अधिक के कर्ज का निवेश कहां हुआ है यह जानने का आम आदमी को पूरा हक है। अभी सरकार जनता में अपनी विश्वसनीयता के सबसे निचले पायदान पर है। इसी विश्वसनीयता के संकट के कारण सरकार पंचायत चुनाव को टालने के लिये हर संभव प्रयास में लग गयी है। क्योंकि जनता में राहुल गांधी के वोट चोरी के चुनाव आयोग पर लगाये आरोपों पर कोई जानकारी नहीं है। मनरेगा योजना में केंद्र ने जो बदलाव किये हैं प्रदेश में उनकी जानकारी शिमला में किये गये धरना प्रदर्शनों से आगे नहीं निकली है। इस समय प्रदेश सरकार को लेकर यह धारणा प्रबल होती जा रही है कि सरकार ने तो परंपरा के मुताबिक हारना ही है। इस हार की आड़ में मुख्यमंत्री कांग्रेस के अन्दर भविष्य के लिये अपने समर्थकों

शेष पृष्ठ 8 पर.....

आरडीजी पर भ्रम फैलाने के बजाय सरकार अपनी तैयारी पर जवाब दे:धूमल

शिमला/शैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश की

वर्तमान आर्थिक स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि प्रदेश में जिस वित्तीय संकट की बात की जा रही है, वह न तो अचानक पैदा हुआ है और न ही अप्रत्याशित है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) का चरणबद्ध रूप से समाप्त होना वर्षो पहले ही तय हो चुका था, फिर भी सरकार ने समय रहते न कोई ठोस रणनीति बनाई और न ही वैकल्पिक संसाधन जुटाने की गंभीर कोशिश की। यह सरकार की दूरदर्शिता की कमी और वित्तीय लापरवाही को दर्शाता है।

प्रो. धूमल ने कहा कि वित्त आयोग की रिपोर्ट में पहले ही साफ कर दिया गया था कि 31 मार्च 2026 के बाद आरडीजी समाप्त हो जाएगी। यह कोई नई या अचानक की गई घोषणा नहीं है। जब यह तथ्य वर्षो से सबके सामने था, तो राज्य सरकार को उसी के अनुरूप अपने खर्च, नीतियां और आय के स्रोत तय करने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करना केंद्र सरकार का संवैधानिक दायित्व होता है, इसलिए इस विषय पर केंद्र पर दोष मढ़ने के बजाये राज्य सरकार को यह बताना चाहिए कि उसने अब तक क्या तैयारी की।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक संकट किसी भी संसाधन-सीमित राज्य में आ सकता है, लेकिन समझदारी इसी में होती है कि समय रहते कठोर और जिम्मेदार फैसले लिये जायें। अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब-जब राज्य को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब उनकी सरकार ने सबसे पहले सख्त वित्तीय अनुशासन लागू किया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खर्चो पर नियंत्रण किया गया, अनावश्यक यात्राओं, सरकारी सुविधाओं और फिजूलखर्ची में कटौती की गई। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर भी सादगी अपनाई और राज्य पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला।

प्रो. धूमल ने कहा कि उनकी सरकार ने केवल खर्च घटाने पर ही नहीं, बल्कि आय बढ़ाने पर भी समान रूप से ध्यान दिया। कृषि और बागवानी क्षेत्र में सुधार कर राज्य की आर्थिकी को मजबूत किया गया। सब्ज़ी उत्पादन और उसके विपणन को प्रोत्साहन देकर जहां पहले यह कारोबार लगभग 250 करोड़ रुपये का था, उसे बढ़ाकर करीब 2250 करोड़ रुपये तक पहुंचाया गया। सेब उत्पादन में आई गिरावट की भरपाई

शेष पृष्ठ 8 पर.....

नाबार्ड से हिमाचल के लिए 713.87 करोड़ की 73 योजनाएं स्वीकृत, विकास कार्यों में आएगी तेजी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए नाबार्ड से 713.87 करोड़ रुपये की 73 योजनाएं स्वीकृत करवाई गई हैं। इनमें 512.31 करोड़ रुपये की 55 योजनाएं लोक निर्माण विभाग और 201.56 करोड़ रुपये की 18 योजनाएं जल शक्ति विभाग से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्राथमिकताएं तय की गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और विधायकों को निर्देश दिए कि स्वीकृत बजट का पूरा उपयोग किया जाए और प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च 2026 से पहले नाबार्ड कार्यालय में जमा हों। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मार्च 2026 तक और अधिक विधायक प्राथमिकता योजनाएं स्वीकृत करवाने के लिए प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद करना पहाड़ी राज्यों के साथ अन्याय है। उन्होंने बताया कि इससे हिमाचल को लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश के पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है, इसके बावजूद प्रदेश के हितों की अनदेखी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद कुशल वित्तीय प्रबंधन, विकास और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी जनहित की मांगें रखी

चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन बबलू ने चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तार के लिए 130 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्तोथर पुल तथा चौकी-मन्यार कॉलेज के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने, जोल में सब फायर स्टेशन स्थापित करने तथा क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने की मांग की।

गगरेट क्षेत्र के विधायक राकेश कालिया ने गगरेट अस्पताल के लिए 2 करोड़ रूपये की राशि प्रदान करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए शेष धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने भद्रकाली आईटीआई भवन एवं छह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने, दौलतपुर चौक एवं मुबारकपुर में सीवरेज सुविधा तथा फ्लड प्रोटेक्शन के लिए समुचित बजट उपलब्ध कराने की मांग की।

ऊना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतपाल सत्ती ने नगर निगम ऊना में शामिल नए गांवों के लिए सीवरेज योजना बनाने, शहर की ड्रेनेज व्यवस्था सुदृढ़ करने, संतोषगढ़-ऊना पुल का निर्माण तथा बीडीओ कार्यालय का कार्य शीघ्र पूर्ण करने की मांग की। उन्होंने भभौर साहिब सिंचाई योजना को सुदृढ़ करने का भी आग्रह किया।

कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा ने जल शक्ति विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए 36.89 करोड़ रूपये तथा नई पेयजल योजनाओं के लिए 14.93 करोड रूपये स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बंगाणा में सीवरेज योजना का कार्य पूर्ण करने, बंगाणा-शांतला तथा थानाकलां-भाखड़ा सड़कों के सुदृढ़ीकरण और बंगाणा में सब जज कोर्ट खोलने की मांग की।

भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने लदरौर-पट्टा पेयजल योजना का निर्माण शीघ्र आरंभ करने, भोरंज नगर पंचायत में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, सब जज कोर्ट के लिए नया भवन तथा सीवरेज योजना बनाने की मांग की। उन्होंने भोरंज में क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए 23.75 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

विधायक रणजीत सिंह ने सुजानपुर बीडीओ कार्यालय एवं पीएचसी चबूतरा के भवन निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया। उन्होंने टौणीदेवी-ऊहल-कक्कड़-जंगलबैरी सड़क के स्तरोन्नयन तथा टौणीदेवी और सुजानपुर अस्पतालों में रिक्त चिकित्सक पदों को भरने की मांग की।

बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बड़सर एवं भोटा में नए बस अड्डों के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, रैली जजरी स्कूल के लिए नया भवन, पीएचसी चकमोह को आरंभ करने की मांग की। उन्होंने दियोटसिद्ध से वॉल्वो बस तथा बड़सर-एम्स बस सेवा शुरू करने का भी आग्रह किया।

पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने हाब्बन घाटी, शिरगुल महाराज एवं भूरेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हाब्बन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने की मांग की।

नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने नाहन मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने तथा स्टाफ नर्सो के रिक्त पद भरने की मांग की। उन्होंने क्षेत्र की तीन सड़कों को स्वीकृति देने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए भोजपुर पुल के निर्माण और कम वोल्टेज की समस्या के समाधान का आग्रह किया।

श्री रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु रेणुकाजी झील की डिसिल्टिंग, रेणुकाजी चिड़ियाघर में शेर लाने की प्रक्रिया तेज करने तथा सड़क नेटवर्क सुदृढ़ करने की मांग की। उन्होंने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान संगड़ाह में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने, ददाहू में कॉलेज भवन व बस स्टैंड निर्माण तथा संगड़ाह में बिजली विभाग का डिविजन खोलने का आग्रह किया।

पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने शिक्षण संस्थानों के निर्माणाधीन भवनों का कार्य शीघ्र पूर्ण करने, हिमाचल-उत्तराखंड को जोड़ने वाले नावघाट पुल का निर्माण जल्द पूरा करने, सड़क नेटवर्क सुदृढ़ करने तथा गिरी सिंचाई नहरों की मरम्मत की मांग की। उन्होंने पांवटा औद्योगिक क्षेत्र में बिजली लोड की समस्या के समाधान का भी आग्रह किया।

कर्म करते रहना और फल की चिंता न करना ही है सरकार की कार्यशैली का आधार : मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने ऊना के कोटला कलां स्थित राधाकृष्ण मंदिर में आयोजित वार्षिक धार्मिक उत्सव में भाग लिया। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना कर बाबा बाल जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमद्भागवत गीता का संदेश कर्म करते रहना और फल की चिंता न करना ही उनकी सरकार की कार्यशैली का आधार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आम लोगों, महिलाओं और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत हिमाचल देश का पहला राज्य बना है, जहां 6,000 निराश्रित बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यार्थी केवल पैसों की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की गई है। इस योजना में 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण केवल एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जनता और भगवान के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश के हक़ और अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। बाबा बाल जी महाराज ने मुख्यमंत्री को शुभाशीर्वाद देते हुए उनके कार्यो की सराहना की।

पेंशनधारकों को 15 फरवरी से पहले ई-केवाईसी कराना अनिवार्य

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों से अपील की है कि वे 15 फरवरी 2026 से पहले अपना ई-केवाईसी सत्यापन अवश्य करवा लें, ताकि उनकी पेंशन बिना रुकावट मिलती रहे। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पेंशन को बैंक या डाकघर खातों में नियमित रूप से भेजने के लिए ऑनलाइन ई-केवाईसी प्रक्रिया लागू की गई है।

यह अभियान जुलाई 2025 में जिला व तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से शुरू किया गया था। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 थी। जिन पेंशनधारकों ने अब तक सत्यापन नहीं कराया है, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो लाभार्थी तय समय तक ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनकी पेंशन स्थायी रूप से बंद की जा सकती है। पेंशनधारक अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए भी संबंधित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

हिमाचल में 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पर 5G सेवाओं का परीक्षण शुरू

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में 5G सेवाओं के मानक अनुरूप संचालन को सुनिश्चित करने के लिए

दूरसंचार विभाग ने 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पर 5G सेवाओं के रोलआउट परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कड़ी में अपर महानिदेशक दूरसंचार, हिमाचल प्रदेश अनिल कुमार गुप्ता और सहायक महानिदेशक अनुपालन नीरज द्वारा ऊना और हमीरपुर शहरों में 5G सेवाओं का विस्तृत परीक्षण किया गया।

दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल द्वारा प्रदेश में 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में 5G सेवाएं शुरू की गई हैं, जिससे राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाएगा। परीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि 5G सेवाएं सभी तकनीकी मानकों के अनुरूप संचालित हो रही हैं, ताकि उपभोक्ताओं को तेज़, सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं मिल सकें।

दूरसंचार विभाग ने स्पष्ट किया कि इस परीक्षण का उद्देश्य 5G नेटवर्क की गुणवत्ता, गति और स्थिरता को परखना है, ताकि भविष्य में आम जनता को बिना किसी बाधा के बेहतर डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। कुल मिलाकर, ऊना और हमीरपुर में 5G सेवाओं का सफल परीक्षण हिमाचल प्रदेश को तकनीक-सक्षम और डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

फोर्टिस अस्पताल मोहाली में क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक बाय-प्लेन न्यूरो कैथ लैब का शुभारंभ

शिमला/शैल। न्यूरो केयर के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में फोर्टिस अस्पताल मोहाली ने

अत्याधुनिक बाय-प्लेन न्यूरो कैथ लैब का शुभारंभ किया है। इस नई सुविधा के साथ फोर्टिस अस्पताल मोहाली उत्तर भारत दिल्ली-एनसीआर के बाद का पहला निजी अस्पताल बन गया है, जहां न्यूरो-इंटरवेंशन के लिए इतनी उन्नत तकनीक उपलब्ध है।

यह बाय-प्लेन न्यूरो कैथ लैब आधुनिक इमेजिंग तकनीक से लैस है, जिसमें एक साथ दो अलग-अलग कोणों से एक्स-रे इमेजिंग की जा सकती है। इससे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की स्पष्ट और विस्तृत 3डी तस्वीरें मिलती हैं, जिससे स्ट्रोक, एन्यूरिज़्म और अन्य न्यूरोवैस्कुलर बीमारियों का तेज़ और सटीक इलाज संभव हो पाता है।

इस लैब की स्थापना डॉ. प्रो. विवेक गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर, इंटरवेंशनल न्यूरोरेडियोलॉजी के नेतृत्व में की गई है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक से आपातकालीन स्थिति में स्ट्रोक मरीजों को सीधे कैथ लैब लाकर तुरंत उपचार शुरू किया जा सकता है, जिससे कीमती समय बचता है और मरीज की जान बचाने की संभावना बढ़ती है।

यह सुविधा न्यूनतम सर्जरी मिनिमल इनवेसिव के माध्यम से सुरक्षित, तेज़ और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करती है और क्षेत्र के मरीजों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

प्रदेश ने तीन वर्षों में अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपये जुटाए:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों में अपने संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। वे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के

विधायकों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का स्वामित्व वापस मिलने से राज्य को लगभग 401 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है और इससे हर वर्ष करीब 20 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। इसके अलावा कड़छम-वांगतू जल विद्युत परियोजना में राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है, जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी।

उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल प्रदेश को कुल 37,199 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान मिला, जो हर वर्ष घटता गया। वर्ष 2021-22 में 10,249 करोड़ रुपये मिले, जो 2025-26 में घटकर 3,257 करोड़ रुपये रह गए। मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने से प्रदेश को लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला हिमाचल जैसे पहाड़ी और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के साथ अन्याय है। इससे विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटा अनुदान बहाल करने और विशेष आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 'बौद्ध सर्किट' की घोषणा की गई है, लेकिन बौद्ध संस्कृति का प्रमुख केंद्र होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश को इससे बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, फिर भी पर्यटन विकास के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया।

बैठक में कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के विधायकों ने सरकार के सामने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी कई अहम मांगें रखीं।

मनाली क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होना प्रदेश के हित में नहीं है, इसलिए इसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने मनाली में आईस स्केटिंग रिंक बनाने, लेफ्ट बैंक सड़क को मजबूत करने, पर्यटन सीजन के दौरान पुलिस बल बढ़ाने और बर्फ हटाने के लिए छोटी मशीनें उपलब्ध कराने की मांग की।

कुल्लू क्षेत्र के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कुल्लू हवाई अड्डे के विस्तार की आवश्यकता बताई। उन्होंने गांवों की सड़कों का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने, मणिकर्ण के लिए वैकल्पिक सड़क बनाने ताकि जाम की समस्या से राहत मिल सके, तथा कुल्लू के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में डॉक्टर और अन्य स्टाफ बढ़ाने की मांग रखी।

बंजार क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि क्षेत्र की सड़कों की हालत सुधारी जानी चाहिए और बिजली की समस्या के समाधान के लिए बजौरा सब-स्टेशन को मजबूत किया जाए। उन्होंने औट-लुहरी सड़क को ठीक करने और लारजी क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का सुझाव भी दिया।

आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोकेंद्र कुमार ने आनी आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में बेहतर सुविधाएं देने, नशे के कारोबार पर सख्त कारवाई करने, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने और बागवानों की मदद के लिए एंटी-हेल गन लगाने की मांग की।

मंडी जिला के करसोग क्षेत्र से विधायक दीपराज ने करसोग आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवन निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने बस सेवाएं बढ़ाने और क्षेत्र की सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही।

सुंदरनगर क्षेत्र के विधायक राकेश जम्वाल ने निहरी और बलग स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण कार्य जल्द पूरा करने, सतलुज नदी से निहरी क्षेत्र के लिए पानी की व्यवस्था करने, डैहर और सुंदरनगर में पानी व सीवरेज की समस्या दूर करने तथा आईटीआई डैहर और सुंदरनगर इंडोर स्टेडियम का निर्माण शीघ्र पूरा करने की मांग की।

नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद कुमार ने आपदा से प्रभावित इलाकों में पैदल पुल बनाने, डिग्री कॉलेज में बन रहे इंडोर स्टेडियम का काम जल्दी पूरा करने और चैलचौक-पंडोह सड़क को सीआरआईएफ के तहत शामिल करने की मांग रखी।

द्रंग क्षेत्र के विधायक पूर्ण सिंह ठाकुर ने सड़कों की हालत सुधारने, बस सेवाएं बढ़ाने, पधर से मंडी फोरलेन के कारण स्थानीय लोगों को हुए नुकसान का समाधान करने और ज्वालापुर स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण में तेजी लाने की बात कही।

जोगिंदर नगर क्षेत्र के विधायक प्रकाश राणा ने बंद पड़ी सड़कों को खोलने, विधानसभा क्षेत्र के आकार के अनुसार कर्मचारियों की तैनाती करने तथा पानी और बिजली की सुविधा बेहतर बनाने की मांग रखी।

धर्मपुर क्षेत्र के विधायक चंद्रशेखर ने जोगिंदर नगर और धर्मपुर को जोड़ने वाले लाल बहादुर शास्त्री पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने, धर्मपुर, संधोल और टिहरा के स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज की सुविधाएं बेहतर करने, धर्मपुर बस अड्डे को हर साल होने वाले नुकसान से बचाने के लिए योजना बनाने और दूध संग्रह केंद्र तथा चिलिंग प्लांट स्थापित करने की मांग की।

बल्ह क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने अपने क्षेत्र में अधूरे पुलों और कलवर्टों का निर्माण जल्द पूरा करने तथा पेयजल परियोजनाओं को मजबूत करने का आग्रह किया।

मंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिल शर्मा ने बड़े वाहनों के लिए मंडी बाईपास सड़क बनाने, मंडी जेल को दूसरी जगह शिफ्ट करने, आपदा में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की समय पर बहाली की सराहना करते हुए टारना स्टोरेज टैंक को अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने और कोटली क्षेत्र में बिजली की समस्या दूर करने की मांग की।

सरकाघाट क्षेत्र के विधायक दिलीप ठाकुर ने सिविल अस्पताल सरकाघाट के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने, डॉक्टरों के खाली पद भरने, निर्माणाधीन पेयजल परियोजना को शीघ्र पूरा करने और आपदा से खराब हुई सड़कों की मरम्मत करने की मांग रखी।

शिमला जिला के चौपाल क्षेत्र से विधायक बलबीर वर्मा ने सैंज-देहा-चौपाल सड़क के सुधारीकरण, सरकारी कार्यालयों में खाली पद भरने और बर्फबारी के समय बेहतर बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की।

बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने एचपीएसईडीसी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की

आउटसोर्स कर्मचारियों के समय पर मानदेय भुगतान के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एचपीएसईडीसी के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में निगम के कामकाज, वित्तीय स्थिति और आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय प्रत्येक माह की 7 तारीख तक जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर भुगतान होना कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें अपने घर-परिवार के खर्च चलाने में किसी तरह की परेशानी न हो। सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बैठक में निगम की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में निगम ने 275 करोड़ रुपये का कारोबार किया और 15 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। वर्ष 2024-25 में निगम का टर्नओवर बढ़कर 300 करोड़ रुपये हो गया और 18 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में 31 दिसंबर, 2025 तक निगम 199.25 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुका है।

मुख्यमंत्री ने निविदा प्रक्रिया को सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए तकनीकी शुल्क में संशोधन के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही निगम का नाम बदलकर 'हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैनपावर एवं ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन' रखने को मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश के युवाओं को देश-विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

बैठक में निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने अंब में 16.26 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के

अंब उपमंडल में 16.26 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र की सड़कों और पुलों की स्थिति बेहतर होगी, जिससे लोगों का आवागमन आसान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने 6.57 करोड़ रुपये की लागत से उन्नत की गई टकारला-बड़ूही वाया नई आबादी सड़क का लोकार्पण किया। करीब 5 किलोमीटर लंबी इस सड़क के सुधरने से क्षेत्र की 11 हजार से अधिक आबादी को लाभ मिलेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यापार से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी।

इसके अलावा उन्होंने लगभग 9.50 करोड़ रुपये की लागत से बनी 6.50 किलोमीटर लंबी अंब-गगरेट-अठवां से हरिजन बस्ती सड़क एवं पुल परियोजना का भी उद्घाटन किया। इससे श्री चिंतपूर्णी और गगरेट विधानसभा क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क मिला है।

मुख्यमंत्री ने टकारला में लगभग 20 लाख रुपये की लागत से बने सामर्थ्य ज्ञानदीप पुस्तकालय एवं व्यायामशाला का भी उद्घाटन किया, जो युवाओं के शैक्षणिक और शारीरिक विकास में सहायक होगा।

इससे पहले उन्होंने अंब में जन समस्याएं भी सुनीं और कई मामलों का मौके पर समाधान किया।

पर्यटन विकास परियोजनाओं पर 2350 करोड़ रुपये खर्च कर रही है प्रदेश सरकार: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में एशियन विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से चल रही पर्यटन विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि राज्य में एडीबी के सहयोग से कुल 2350 करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें ट्रेंच-1 के तहत 1620 करोड़ रुपये और ट्रेंच-2 के तहत 730 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य विश्व-स्तरीय गुणवत्ता के साथ तय समय में पूरे किए जाएं।

उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। पालमपुर और नगरोटा बगवां में एडीबी के सहयोग से 77.70 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें पार्किंग, सौंदर्यकरण, सड़क सुधार और धार्मिक व पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है। इसके अलावा हमीरपुर, जिला के श्री बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में 51.09 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सौंदर्यीकरण व अधोसंरचना विस्तार कार्य, जिला कांगड़ा के धर्मशाला में 33.78 करोड़ रुपये की लागत से आइस स्केटिंग रिंक व रोलर स्केटिंग रिंक, कुल्लू में 20.57 करोड़ रुपये की लागत से वेलनेस सेंटर तथा मनाली में 36.19 करोड़ रुपये की लागत से वेलनेस सेंटर, 8.63 करोड़ रुपये की लागत से कुल्लू स्थित नग्गर कैसल का संरक्षण व जीर्णोद्धार इत्यादि कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि शिमला में आईस स्केटिंग रिंक व रोलर स्केटिंग रिंक, मनाली में आईस स्केटिंग रिंक, कालेश्वर महादेव मंदिर कून्हा में जन-सुविधाएं, हमीरपुर जिला के नादौन में राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य सुविधाएं तथा वेलनेस सेंटर व साहसिक खेल केन्द्र एवं छात्रावास का निर्माण, नगरोटा बगवां में वेलनेस सेंटर व म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण एशिएन विकास बैंक के सहयोग से किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने पर्यटन विकास बोर्ड के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी दी और सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला विकास निगम की 52वीं बैठक आयोजित

महिलाओं के स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा तीन लाख रुपये की गई

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में महिला विकास निगम की 52वीं निदेशक मंडल बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लेते हुए स्वरोज़गार ऋण की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने को मंजूरी दी गई। इस फैसले से अधिक से अधिक महिलाएं अपना स्वरोज़गार शुरू कर सकेंगी और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी।

इसके अलावा महिला कल्याण, कौशल विकास, रोज़गार सृजन, प्रशिक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। निदेशक मंडल ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

महिला विकास निगम महिलाओं के सर्वांगीण विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है और भविष्य में भी प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास जारी रखेगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्याम भगत नेगी, महिला विकास निगम के प्रबंध निदेशक अजय कुमार यादव सहित निदेशक मंडल के सदस्य उपस्थित रहे।

अंतरात्मा के मामलों में, बहुमत के कानून का कोई स्थान नहीं है।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

आरडीजी की समाप्ति और वित्तीय संकट का असली चेहरा

हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति आज किसी एक फैसले या एक वर्ष की उपज नहीं है, बल्कि वर्षों की लापरवाही, अव्यावहारिक वादों और कमजोर वित्तीय अनुशासन का परिणाम बन चुकी है। सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालते समय जिस ''व्यवस्था परिवर्तन'' का नारा दिया था, वह आज अपने ही बोझ तले दबता दिखाई दे रहा है। संविधान के तहत चलने वाली स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय नियमों और जवाबदेही के ढांचे से ऊपर आखिर क्या बदला जाना था, यह सवाल आज भी प्रदेश की जनता के सामने अनुत्तरित है। जनता ने कांग्रेस को सत्ता इसलिए सौंपी थी क्योंकि वह पिछली सरकार से असंतुष्ट थी और कांग्रेस ने दस गारंटियों के रूप में एक वैकल्पिक भरोसा प्रस्तुत किया था। लेकिन सत्ता में आते ही जिस तरह श्रीलंका जैसे हालात की चेतावनी देकर भय का माहौल बनाया गया, उससे यह उम्मीद बनी थी कि सरकार खर्च पर लगाम लगाएगी और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देगी। व्यवहार में हुआ ठीक इसके विपरीत।

राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी की समाप्ति ने सरकार की असल तैयारी और सोच को पूरी तरह उजागर कर दिया है। आरडीजी कोई स्थायी आय का साधन नहीं था, बल्कि सीमित अवधि के लिए दी जाने वाली राहत थी, जिसकी समाप्ति पूर्वनिर्धारित थी। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं और खर्च संरचना को इस अनुदान पर निर्भर बना लिया। अब जब यह सहायता बंद हुई है, तो संकट के लिए केंद्र को दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है, जबकि वास्तविक समस्या राज्य के भीतर है। बीते तीन वर्षों में सरकार ने जनता पर करों और उपकरों का भारी बोझ डालकर करोड़ों रुपये अतिरिक्त राजस्व जुटाया, फिर भी वित्तीय संतुलन नहीं बन पाया। जब सरकार सत्ता में आई थी, तब प्रदेश का कर्ज लगभग 76 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। यह कर्ज किस विकास में लगा, इसका ठोस और पारदर्शी विवरण आज तक जनता के सामने नहीं रखा जा सका है।

कैग रिपोर्ट ने इस वित्तीय अव्यवस्था की पुष्टि आधिकारिक तौर पर कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे प्रतिबद्ध खर्चों में जा रहा है, जबकि विकासात्मक कार्यों के लिए सीमित धन ही बच पा रहा है। नियमों के तहत कर्ज केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए लिया जाना चाहिए जिनसे भविष्य में आय उत्पन्न हो, लेकिन हिमाचल में विकास के नाम पर लिया गया कर्ज रोजमर्रा के खर्चों की भरपाई में झोंका जा रहा है। यही कारण है कि भारी कर्ज और बढ़े हुए करों के बावजूद कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है।

सरकार की गारंटियों की जमीनी हकीकत भी वित्तीय प्रबंधन की कमजोरी को उजागर करती है। प्रतिवर्ष एक लाख रोजगार देने का वादा बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों के सामने दम तोड़ता नजर आता है। महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सिमट गई है। अन्य गारंटियों में लगातार शर्तें जोड़कर उनके दायरे को कम किया जा रहा है। यह सवाल अब स्वाभाविक है कि क्या कांग्रेस को सत्ता में आने से पहले प्रदेश की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं था, या फिर सत्ता प्राप्ति के लिए जानबूझकर ऐसे वादे किए गए जिन्हें निभाना संभव ही नहीं था।

वित्तीय संकट के बीच सरकार के फैसले विरोधाभासों से भरे रहे हैं। एक ओर जनता से त्याग की अपील की जाती है, दूसरी ओर राजनीतिक नियुक्तियां, सलाहकारों की नियुक्ति, निगमों और बोर्डों में मानदेय वृद्धि और प्रशासनिक खर्च लगातार बढ़ते रहे हैं। जिसका सीधा असर प्रदेश की वित्तीय सेहत पर पड़ना स्वाभाविक है।

आरडीजी की समाप्ति के बाद आने वाला समय हिमाचल के लिए और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ऐसे में वेतन, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं का सुचारु संचालन सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है।

हिमाचल की वित्तीय हकीकत अब नारों और आरोप-प्रत्यारोप से परे है। आरडीजी की समाप्ति कोई अचानक आया तूफान नहीं है, बल्कि पहले से तय प्रक्रिया थी, जिसके लिए समय रहते तैयारी की जा सकती थी। लेकिन सरकार ने खर्च नियंत्रण, राजस्व बढ़ाने और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन की बजाय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी। परिणामस्वरूप आज प्रदेश कर्ज, करों और अनिश्चित भविष्य के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। यदि अब भी ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट केवल सरकार का नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल के भविष्य का संकट बन जाएगा।

सीपीआई के आधार वर्ष में बदलाव क्या बदला है और यह क्यों ज़रूरी है

सौरभ गर्ग
सचिव सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

महंगाई देश के सबसे अहम आर्थिक संकेतकों में से एक है, जिसे आम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीधे महसूस करते हैं, जैसे घर का राशन, किराया और पेट्रोल-डीज़ल के खर्च में बढ़ोतरी से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) इसी महंगाई को मापता है। यह उन चीज़ों और सेवाओं के दाम देखता है, जिनका इस्तेमाल आम परिवार रोज़ करता है। सरल शब्दों में, सीपीआई आम आदमी की ज़िंदगी का आईना है। यह बताता है कि थाली में खाने का खर्च कितना बढ़ा, घर का किराया कितना हुआ, और काम पर जाने के लिए ईंधन कितना महंगा हुआ।

सीपीआई भले ही एक आंकड़ा लगता हो, लेकिन यह सरकार को यह समझने में मदद करता है कि लोगों पर महंगाई का असली असर क्या है। इसी आधार पर वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसले किए जाते हैं, ताकि ज़रूरी चीज़ें आम लोगों की पहुंच में बनी रहें।

भारतीय रिज़र्व बैंक भी ब्याज दर और महंगाई को नियंत्रित करने जैसे फैसलों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई को ही सबसे मुख्य पैमाना मानता है। इसलिए जब सीपीआई ज़मीन की हकीकत सही तरीके से दिखाता है, तब सरकार और आरबीआई की नीतियाँ भी लोगों की असली परेशानियों के अनुसार बेहतर बन पाती हैं। महंगाई सिर्फ दाम बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह भी है कि दामों में बदलाव से घर के बजट पर कितना असर पड़ता है। इसलिए जितना ज़रूरी दामों को मापना है, उतना ही ज़रूरी यह भी है कि महंगाई का सूचकांक लोगों की आज की खर्च करने की आदतों को सही तरीकेसे दिखाए। इसी संदर्भ में भारत में सीपीआई के आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 किया जा रहा है। पिछली बार आधार बदले जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। शहरों की आबादी बढ़ी है, सेवाओं का क्षेत्र बढ़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण खरीदारी का तरीका बदला है और घरों का खर्च अब कई नई चीजों पर होने लगा है।

इसीलिए नया सीपीआई 2024 तैयार करने में 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। समय के साथ लोगों की ज़रूरतें और खर्च बदलते हैं, इसलिए सीपीआई में अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं को दी जाने वाली अहमियत भी बदली गई है। जिन चीजों पर अब परिवार ज्यादा खर्च करते हैं, उन्हें सीपीआई में ज्यादा महत्व दिया गया है, और जिन पर खर्च कम हो गया है, उन्हें कम महत्व दिया गया है।

इससे सीपीआई वही महंगाई दिखाता है, जो सच में आम परिवार के बजट को प्रभावित करती है। साथ ही, उपभोग की टोकरी (कंजम्पशन बास्केट) को भी बदला गया है, ताकिसेवाओं पर बढ़ते खर्च जैसे नए रुझान दिखाई दे सकें, जो बढ़ती आय और बदलती जीवनशैली की वजह से बढ़ रहे हैं। सीपीआई को मापने का तरीका अपडेट करना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना यह तय करना कि उसमें क्या-क्या शामिल किया जाए।

नया संशोधित सीपीआई अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के ज्यादा करीब है, लेकिन इसमें भारत से जुड़ी खास बातें भी बनी हुई हैं। इससे भारत की महंगाई की तुलना दूसरे देशों से करना आसान हो जाता है। आम परिवार के लिए इसका मतलब यह है कि सरकार और नीति बनाने वाले लोग यह बेहतर समझ पाते हैं कि भारत में दामों में होने वाला बदलाव दुनिया के हालात से कैसे जुड़ा है, और साथ ही यह भी ध्यान रहता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है।

सीपीआई के लिए आंकड़े जुटाने का तरीका भी अब लोगों की बदलती खरीदारी और खर्च की आदतों के अनुसार बेहतर बनाया गया है। जहां पहले की तरह बाजारों से दाम इकट्ठा किए जाते रहेंगे, खासकर खाने-पीने और ज़रूरी चीज़ों के, वहीं 2024 के नए ढांचे में अब कुछ सेवाओं के ऑनलाइन दाम भी शामिल किए जा रहे हैं। जैसे मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं, हवाई टिकट और कुछ अन्य सेवाओं के दाम अब ऑनलाइन स्रोतों से भी लिए जाएंगे। नई सीपीआई श्रृंखला में अब कंप्यूटर की मदद से दाम इकट्ठा किए जा रहे हैं। इससे हाथ से होने वाली गलतियाँ कम हुई हैं और तुरंत जाँच भी हो जाती है। इससे दामों से जुड़े आंकड़ों की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता दोनों बेहतर हुई हैं। सीपीआई के आंकड़े सही और समय पर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर ऐसे फैसले होते हैं, जो सीधे आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, जैसे कर्ज कितना महंगा होगा, बचत पर कितना ब्याज मिलेगा, और बढ़ती महंगाई से घर का बजट कैसे प्रभावित होगा। नए आधार वर्ष की सीपीआई में अब कई मामलों में सरकारी स्रोतों से मिलने वाले आधिकारिक आंकड़ों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे रेल किराया, डाक शुल्क, ईंधन के दाम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाली चीजें। इससे इन दामों को पहले से ज्यादा सही तरीके से दर्ज किया जा रहा है और बाजार सर्वे में होने वाली गलती या पक्षपात की संभावना भी कम हो जाती है।

अब सर्वे के आंकड़े, सरकारी रिकॉर्ड और डिजिटल माध्यमों से मिलने वाले दाम, तीनों को मिलाकर सीपीआई तैयार की जा रही है। यह पुरानी व्यवस्था की तुलना में बड़ा सुधार है और इससे दामों में होने वाले बदलाव की ज्यादा भरोसेमंद तस्वीर मिलती है। इतने बड़े स्तर पर सीपीआई के आधार वर्ष में बदलाव करना एक बहुत बड़ा संस्थागत प्रयास होता है। इसमें देश भर के फील्ड दफ्तरों, सांख्यिकी विभागों और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्थाओं के बीच तालमेल जरूरी होता है। इस पूरी प्रक्रिया में मेथडोलॉजी की गहराई से जांच की जाती है, अलग-अलग विकल्पों को परखा जाता है और अर्थशास्त्रियों व विषय-विशेषज्ञों से सलाह ली जाती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने विशेषज्ञ समूहों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत की है, ताकि किए गए बदलाव साफ, समझने में आसान और वैज्ञानिक रूप से सही हों। टोकरी, वेटेज और आंकड़ों के स्रोत बदलने के बाद भी सीपीआई का मूल उद्देश्य वही रहता है-यानी एक परिवार की नज़र से दामों में होने वाले बदलाव को दिखाना। यह निरंतरता इसलिए ज़रूरी है, ताकि हम समय के साथ महंगाई की तुलना कर सकें। सीधे शब्दों में, सीपीआई को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर ही रखा गया है, ताकि वह नीति बनाने वालों के लिए एक भरोसेमंद मार्गदर्शक बना रहे। सीपीआई हमें यह याद दिलाता है कि हर आंकड़े के पीछे करोड़ों लोगों की असली ज़िंदगी छिपी होती है। आखिरकार, आंकड़े लोगों के लिए ही होते हैं। यह चुपचाप यह दिखाता है कि दामों में बदलाव हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है और सरकार की नीतियों को दिशा देता है। आधार वर्ष में चल रहे संशोधन के ज़रिये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि सीपीआई सही, समय के अनुसार अपडेट और लंबे समय तक एक-जैसे तरीके से मापा गया रहे। ताकि सीपीआई सिर्फ एक संख्या न होकर, पूरे देश के लोगों की असली ज़िंदगी की सच्चाई दिखाने वाला आईना बना रहे।

मिट्टी की मर्यादा और जल की तपस्या से सजेगा ''हरित भविष्य''

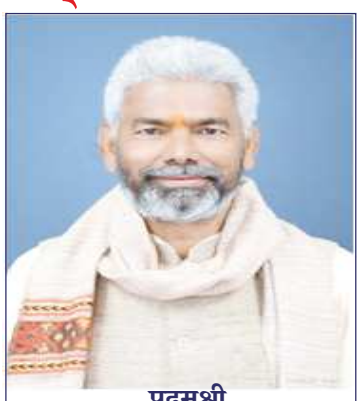

पद्मश्री
उमाशंकर पांडेय

भारतीय कृषि की गाथा आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। दशकों पहले हमने खाद्यान्न की कमी वाले देश से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों और निर्यातकों की कतार में अपनी जगह बनाई। यह हमारी मेहनत और बेहतर बीजों, सिंचाई के विस्तार व रासायनिक उर्वरकों का ही परिणाम था। लेकिन आज जब मैं अपने गांव जखनी, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश की मिट्टी को छूता हूं, तो विशेषज्ञ एक गंभीर चेतावनी देते सुनाई देते हैं। वे कहते हैं कि जिस रासायनिक बैसाखी के दम पर हमने तरक्की की, उसने हमारी मिट्टी और पाताल के पानी को गहरा जख्म दिया है।

'साइलेंट वेल्थ' पर अदृश्य संकट

मिट्टी सिर्फ धूल नहीं, बल्कि देश की ''साइलेंट वेल्थ'' मौन संपदा है, जो हमारी पूरी खाद्यन्न व्यवस्था की नींव है । लेकिन यूरिया जैसे नाइट्रोजन उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग ने इस संपदा को खोखला कर दिया है। आज हमारी मिट्टी में सिर्फ मुख्य पोषक तत्वों की ही नहीं, बल्कि सल्फर, जिंक और बोरॉन जैसे सूक्ष्म तत्वों की भी भारी कमी हो गई है। नतीजा हमारे सामने है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट रही है और खेतों की पैदावार थम सी गई है।

हमें अब '4_R' के मंत्र को जीवन में उतारना होगा सही स्रोत Right Source, सही खुराक Right Dose, सही समय Right Time और सही स्थान Right Place । यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि मिट्टी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है ताकि पोषक तत्वों की बर्बादी न हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे।

जखनी का अनुभव हर खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ मेरी जीवन यात्रा सूखे से जूझते बुंदेलखंड के जखनी गांव से शुरू हुई । साल 2005 में जब कोई सरकारी सहायता नहीं थी। बारिश के साथ बहती मिट्टी को खेत में रोकने के लिए कोई योजना भी नहीं थी। तब हमने सामुदायिक एकजुटता से परंपरागत जल संरक्षण ''खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड'' का अभियान शुरू किया । हमारा लक्ष्य सीधा था। बारिश की हर बूंद को खेत में रोकना और धरती की कोख (एक्वीफर) को फिर से भरना ।

आज गर्व होता है कि नीति आयोग ने इस ''जखनी मॉडल'' को सराहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेड़बंदी सहित परंपरागत तरीके से जल संरक्षण के लिए देशभर के सरपंचों को पत्र लिखा। जिस बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट जैसे जिलों में कभी गर्मियों में रेलगाड़ी से पानी आता था, वहां मेड़बंदी के कारण भू-जल स्तर में 1.34 मीटर तक का सुधार देखा गया है । लेकिन एक डर हमेशा बना रहता है। यदि हम जल तो बचा लें, पर उर्वरकों और रसायनों के जहर से मिट्टी को न बचा पाए, तो यह सारी मेहनत बेकार जाएगी। जल संरक्षण के साथ जैविक और प्राकृतिक खेती का संगम ही किसानों के लिए ''सोने पर सुहागा'' साबित होगा।

एकीकृत पोषण परंपरा और तकनीक का मेल भविष्य की कृषि का आधार एकीकृत पोषण प्रबंधन (INM) है। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम उर्वरकों को पूरी तरह त्याग दें, बल्कि उन्हें जैविक खाद, बायो-फर्टिलाइजर और सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ संतुलित करें। सरकार भी इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। फर्मेंटेड जैविक खाद (FOM) और मोलासेस से निकलने वाले पोटाश (PDM) को अब उर्वरक सब्सिडी के दायरे में लाया गया है, ताकि मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल सुधारा जा सके ।

तकनीक भी अब किसान के दरवाजे पर है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC) अब महज एक कागज नहीं, बल्कि किसान का गाइड बन रहा है । इसे ''डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर'' (DBT) से जोड़ने की योजना है, जिससे हर खेत को उसकी जरूरत के हिसाब से ''पर्सनलाइज्ड'' सलाह मिल सकेगी। गांवों में बन रहे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSKs) अब खेती के ''वन-स्टॉप हब'' बन रहे हैं, जहां खाद से लेकर विशेषज्ञ सलाह तक सब एक छत के नीचे उपलब्ध है।

नैनो क्रांति और नीतिगत सुधार

भारत आज नैनो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नैनो यूरिया और लिक्विड बायो-फर्टिलाइजर जैसे उत्पाद न केवल बर्बादी रोकते हैं, बल्कि पैदावार भी बढ़ाते हैं। ''पीएम-प्रणाम'' (PM-PRANAM) जैसी योजनाएं राज्यों को रासायनिक खादों का मोह छोड़ने और वैकल्पिक पोषक तत्वों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। साथ ही, कृषि में ड्रोन का प्रवेश ''प्रिसिजन फार्मिंग'' यानी सटीक खेती के सपने को सच कर रहा है ।

हालांकि, चुनौतियां अभी शेष हैं। यूरिया पर अत्यधिक सब्सिडी के कारण संतुलन अभी भी बिगड़ा हुआ है। हमें ऑर्गेनो-मिनरल फर्टिलाइजर (OMFS) के लिए एक स्पष्ट नियामक ढांचा चाहिए, ताकि खनिज और जैविक तत्वों का दोहरा लाभ खेतों तक पहुंच सके।

एक लचीला भविष्य

जैसे-जैसे भारत विकास के पथ पर अग्रसर होगा, सरकार, उद्योग व खेती करने वाले लोगों के बीच तालमेल बहुत जरूरी होगा। 4_R के सिद्धांत को रसायनिक खादों के लिए अपनाने, खेती में आधुनिक तकनीक के विस्तार से बदलाव लाये जा सकते आज मिट्टी की सेहत को प्राथमिकता देकर, भारत का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 2026 की देहरी पर खड़े होकर जब हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो उसका रास्ता हमारे खेतों की मेड़ों से होकर ही जाता है।

विकसित भारत 2047 की ओर स्मार्ट रास्ता – हड़ताल नहीं, बल्कि श्रम संहिता

डॉ. दीपक जायसवाल
अध्यक्ष
भारतीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मोर्चा

पीढ़ियों से, भारत के श्रमिकों ने एक पुरानी और टुकड़ों में बंटी श्रम प्रणाली का बोझ उठाया है, जो अक्सर उनके वेतन, सुरक्षा और कार्यस्थल पर गरिमा की रक्षा करने में विफल रही है। असंगठित, संविदा और उभरते गिग क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक नीति-परिदृश्य में अदृश्य रहे हैं और बुनियादी सामाजिक सुरक्षा से वंचित रहे हैं। चार श्रम संहिताएं इन ऐतिहासिक अन्यायों का सुधार करने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित प्रयास का प्रतिनिधित्व करती हैं। लगभग तीन दर्जन अलग -अलग कानूनों को एक सुसंगत, एकल ढांचे में लाकर, ये संहिताएं न्यायसंगत वेतन, सुरक्षित कार्यस्थल और उन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं, जो लंबे समय से वंचित रहे हैं। वर्षों के परामर्श और बहस के बाद इनका कार्यान्वयन, श्रमिकों के अधिकारों को मजबूत करने तथा अधिक स्थिर और मानवतापूर्ण रोजगार वातावरण बनाने में निर्णायक क्षण का प्रतीक है।

एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में, भारतीय ट्रेड यूनियनों का राष्ट्रीय मोर्चा (एनएफआईटीयू), कामगारों की दीर्घकालिक भलाई, गरिमा और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मोर्चा दृढ़ता से मानता है कि 12 फरवरी को श्रम संहिताओं के खिलाफ हड़ताल में भाग लेना न तो आवश्यक है और न ही वर्तमान समय में श्रमिक वर्ग के सर्वोत्तम हित में है।

श्रम संहिताएं कोई अचानक या एकतरफा हस्तक्षेप नहीं हैं। ये दो दशकों से अधिक समय तक चली सुधार प्रक्रिया का परिणाम हैं। 29 अलग-अलग श्रम कानूनों को चार व्यापक संहिताओं में समेकित करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी, ताकि अनुपालन को सरल बनाया जा सके, अस्पष्टता को कम किया जा सके तथा कार्य और रोजगार की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप भारत की श्रम रूपरेखा को आधुनिक बनाया जा सके।

श्रम संहिताओं को पूरी तरह खारिज करना उन मौलिक लाभों की उपेक्षा करता है, जो वे श्रमिकों को प्रदान करने का प्रयास करती हैं। वेतन संहिता सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन कवरेज और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करती है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से मौजूद वेतन सुरक्षा के अंतर को दूर किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, पहली बार, असंगठित, संविदा, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की विधायी रूपरेखा तैयार करती है। इन श्रमिकों की संख्या लगभग 40 करोड़ है और पहले ये श्रमिक औपचारिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे। ये प्रावधान भारत में श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का ऐतिहासिक विस्तार प्रस्तुत करते हैं।

औद्योगिक संबंध संहिता तथा पेशे से जुड़ी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-परिस्थिति संहिता का उद्देश्य औद्योगिक सद्भाव, तेज विवाद निवारण और सुरक्षित, स्वस्थ व अधिक सम्मानजनक कार्यस्थलों को बढ़ावा देना है। कुछ प्रावधानों को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, अनुभव बताते हैं कि व्यापक विरोध और हड़तालों से शायद ही रचनात्मक परिणाम मिलते हैं। संवाद, नियम-आधारित सुधार और मुद्दा-विशेष पर चर्चा के जरिये श्रमिकों के हित बेहतर तरीके से पूरे किये जा सकते हैं, बजाये इसके कि आपस में टकराव हो, जिससे पारिश्रमिक हानि, उत्पादन में रुकावट और रोजगार असुरक्षा का जोखिम पैदा होता है-विशेष रूप से श्रम बल के सबसे कमजोर वर्गों के लिए।

यह दावा करना भी गलत है कि श्रम संहिताएं बिना परामर्श के लागू की गई हैं। सुधार प्रक्रिया में त्रिपक्षीय चर्चाओं के कई दौर, संसद की स्थायी समितियों में विचार-विमर्श और विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद शामिल थे। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में, मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें बातचीत और संस्थागत संवाद के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, न कि उन व्यवधानों के द्वारा जो अंततः स्वयं श्रमिकों को ही नुकसान पहुंचाते हैं।

जब भारतीय अर्थव्यवस्था संरचनात्मक रूपांतरण के दौर से गुजर रही है और राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है, श्रमिक संघों को विघटन के बजाय जिम्मेदार कारवाई का चयन करना चाहिए। हमारी भूमिका केवल सुधारों का विरोध करना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह आकार देना है कि श्रमिकों के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर गरिमा को प्रभावी क्रियान्वयन और सतत सुधार के माध्यम से व्यावहारिक तौर पर मजबूत किया जा सके।

श्रमिक संघों की वास्तविक जिम्मेदारी केवल विरोध करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि मजदूरों को वास्तविक रूप में जमीनी स्तर पर लाभ हो। अब ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि श्रम संहिताओं को न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जाए और इन्हें हर उस मजदूर तक पहुंचाया जाए, जिसे सुरक्षा की आवश्यकता है। हड़ताल की बजाये संवाद, सहयोग और निरंतर सुधार चुनकर, श्रमिक संघ एक ऐसा प्रणाली बनाने में मदद कर सकते हैं, जो श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और गरिमा प्रदान करती हो और साथ ही 2047 तक विकसित भारत की ओर देश की यात्रा का भी समर्थन करती हो।

धार्मिक आस्था, विश्वास और पर्यटन का केंद्र बनता तत्तापानी

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के करसोग क्षेत्र में सतलुज नदी के किनारे बसा तत्तापानी अब केवल एक धार्मिक स्थल भर नहीं रह गया है। प्राकृतिक गर्म पानी के चश्मों, गहरी आस्था और उभरती पर्यटन गतिविधियों के कारण यह क्षेत्र तेजी से एक ऐसे पर्यटन गंतव्य के रूप में पहचान बना रहा है, जहां अध्यात्म, स्वास्थ्य और साहसिक अनुभव एक-दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं।

शिमला से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित तत्तापानी सदियों से अपने गंधकयुक्त गर्म पानी के प्राकृतिक चश्मों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इन चश्मों का जल औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यहां स्नान करने से चर्म रोग, जोड़ों के दर्द और अन्य शारीरिक व्याधियों से राहत मिलती है। इसी विश्वास के चलते दूर-दराज़ से श्रद्धालु और स्वास्थ्य लाभ की कामना करने वाले लोग यहां पहुंचते रहे हैं।

तत्तापानी का धार्मिक महत्व इसकी प्राचीन आस्थाओं से गहराई से जुड़ा है। यह क्षेत्र सप्तऋषियों में से एक ऋषि जमदग्नि की तपोस्थली माना जाता है। मान्यता है कि यहां गर्म पानी के कुंडों में स्नान करने से कुंभ स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य के उत्तरायण होने पर यहां विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस अवसर पर तुलादान की परंपरा भी निभाई जाती है, जिसमें श्रद्धालु अन्न, वस्त्र और अन्य सामग्री का दान करते हैं।

कोल डैम परियोजना के बाद तत्तापानी क्षेत्र में बनी झील ने यहां के पर्यटन स्वरूप को एक नया आयाम दिया है। शांत जलराशि के बीच मोटर बोटिंग, जेट स्की और हॉट एयर बैलून जैसी जलक्रीड़ा और साहसिक गतिविधियां शुरू होने से तत्तापानी अब युवाओं और रोमांच पसंद करने वाले पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय हो रहा है। इन गतिविधियों से न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं।

राज्य सरकार द्वारा तत्तापानी को एक संगठित पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कोल डैम प्रबंधन के साथ हुई बैठकों में प्राकृतिक गर्म पानी के चश्मों को पुनर्जीवित करने, पुराने कुंडों की स्थिति सुधारने और उनमें जल प्रवाह को संतुलित बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, ताकि धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रभावित किए बिना क्षेत्र का विकास किया जा सके।

तत्तापानी की खासियत केवल इसके कुंडों या जलक्रीड़ा गतिविधियों तक सीमित नहीं है। चारों ओर फैली हरियाली, सतलुज नदी का शांत प्रवाह और पहाड़ी परिवेश इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आकर्षक बनाता है। श्रद्धालु, पर्यटक और साहसिक गतिविधियों के शौकीन-तीनों वर्गों के लिए तत्तापानी में अलग-अलग अनुभव मौजूद हैं।

तत्तापानी वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव प्रेम रैना का कहना है कि धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक मान्यताएं, औषधीय जल और झील में संचालित जलक्रीड़ा गतिविधियां मिलकर इस स्थान को एक विशिष्ट पर्यटन पहचान दे रही हैं। उनके अनुसार यदि आधारभूत सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और सुनियोजित विकास पर निरंतर ध्यान दिया गया, तो तत्तापानी आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है।

आज तत्तापानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां परंपरा और आधुनिक पर्यटन एक-दूसरे के पूरक बनते दिखाई दे रहे हैं। संतुलित विकास, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय सहभागिता के साथ यह क्षेत्र न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना रह सकता है, बल्कि स्वास्थ्य और साहसिक पर्यटन का एक आदर्श मॉडल भी बन सकता है।

क्या भाजपा सांसद और विधायक उठाएंगे हिमाचल के अधिकारों की आवाज:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बरठीं में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र

सरकार और भाजपा पर हिमाचल के अधिकारों को दबाने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 73 वर्षों से हिमाचल को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान को बंद करना प्रदेश के साथ अन्याय है। मुख्यमंत्री ने तीखे लहजे में पूछा क्या भाजपा के सांसद और विधायक उस लगभग 50 हजार करोड़ रुपये की आवाज उठाएंगे, जो आने वाले वर्षों में हिमाचल को नहीं मिलेगा?

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की 68 प्रतिशत भूमि वन क्षेत्र है और लोग केवल 32 प्रतिशत जमीन पर जीवन यापन करते हैं, फिर भी केंद्र सरकार ने इस सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने एक फरवरी को हिमाचल के इतिहास का काला दिन बताया। सुक्खू ने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल सरकार की नहीं, बल्कि प्रदेश के हर नागरिक के अधिकारों की है।

ओपीएस पर उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तब तक पुरानी पेंशन योजना बंद नहीं होगी, चाहे केंद्र सरकार कितनी ही आर्थिक मदद रोक दे। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने तीन साल में 23 हजार करोड़ रुपये कर्ज लिया, लेकिन 26 हजार करोड़ रुपये का मूलधन और ब्याज चुकाया भी है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने कर्ज बढ़ाने के साथ संसाधन नहीं जुटाए।

मुख्यमंत्री ने आपदा राहत, मछुआरों की रॉयल्टी में कटौती, बेसहारा पशुओं के लिए सहायता बढ़ाने और विकास कार्यों की कई घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी का दर्द बांटना ही असली व्यवस्था परिवर्तन है और हिमाचल के हक़ की लड़ाई जनता के साथ मिलकर लड़ी जाएगी।

राज्य में जियोथर्मल ऊर्जा की संभावनाएं तलाशने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार और जियोट्रॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच राज्य में जियोथर्मल ऊर्जा की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक समझौता ज्ञापन एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। यह कदम राज्य को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ और सतत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। जियोथर्मल ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का बेहतर विकल्प है और इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कंपनी को जियोथर्मल ऊर्जा के अन्वेषण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।

इस समझौते से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के नए अवसर खुलेंगे। समझौता ज्ञापन पर प्रदेश सरकार की ओर से ऊर्जा निदेशालय के मुख्य अभियंता डी.पी. गुप्ता और कंपनी की ओर से चेयरपर्सन टोमस ओल्टो हेनसन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और भारत में आइसलैंड के राजदूत बेनेडिक्ट होस्कुल्डसन भी उपस्थित रहे।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एआई ऐप लॉन्च

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बिलासपुर जिला प्रशासन की अभिनव पहल 'पढ़ाई विद एआई' ऐप का बरठीं में विधिवत शुभारंभ किया। यह एआई आधारित डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म विशेष रूप से जिला बिलासपुर के उन विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जुड़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक ही मंच पर उपलब्ध होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को नई दिशा देने और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और सभी विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने 'पढ़ाई विद एआई' को विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक दूरदर्शी पहल बताते हुए कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से बच्चों को घर बैठे पढ़ाई की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ऐप के माध्यम से डिजिटल शिक्षण सामग्री के साथ-साथ नियमित अकादमिक काउंसलिंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन मिल सकेगा।

उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि एनटीपीसी के सहयोग से इस ऐप को विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के दिए निर्देश

डीएचएस में 300 डॉक्टरों का प्रशिक्षण व अवकाश रिजर्व कोटा बनेगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि अप्रैल से राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक और विश्वस्तरीय चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे मरीजों को बेहतर जांच और उपचार की सुविधाएं मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और जरूरत के अनुसार नए पद भी सृजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आईजीएमसी शिमला में जल्द ही पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। वर्तमान में चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में 300 डॉक्टरों का प्रशिक्षण और अवकाश रिजर्व कोटा बनाने के निर्देश दिए, ताकि पीजी कोर्स के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों से सेवाएं प्रभावित न हों। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों में छोटे बैच रखने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी कक्षा में 60 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि लोगों को इलाज के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश सरकार सुगम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आईटी आधारित समाधानों पर दे रही बल:डॉ. धनी राम शांडिल

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुगम, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए आईटी आधारित समाधानों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्री ने बताया कि सुगम स्वास्थ्य मोबाइल एप और वेब आधारित हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम 'ई-सुश्रुत' के माध्यम से मरीजों को पंजीकरण, ओपीडी-आईपीडी सेवाएं, बिलिंग, जांच, भर्ती-डिस्चार्ज और दवा प्रबंधन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। इन प्रणालियों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।

उन्होंने बताया कि पायलट आधार पर राज्य के 53 अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू की गई है, जहां अब तक लाखों ओपीडी और आपातकालीन पंजीकरण किए जा चुके हैं। सभी अस्पतालों को आवश्यक आईटी उपकरण और टैबलेट उपलब्ध करवाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक से मरीजों और चिकित्सकों दोनों को लाभ मिल रहा है और राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो रही है।

हिमुडा किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध:राजेश धर्माणी

शिमला/शैल। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमाचल

प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) की निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हिमुडा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लोगों को किफायती और बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है तथा राज्य में योजनाबद्ध टाउनशिप के विकास को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि बढ़ती आवासीय मांग को देखते हुए राज्य सरकार कई महत्वाकांक्षी टाउनशिप परियोजनाएं शुरू कर रही है। बैठक में सोलन जिले के बद्दी के शीतलपुर में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ टाउनशिप, पच्छाद के मोरनी हिल्स और कांगड़ा एयरपोर्ट के पास लुंज में प्रस्तावित नई टाउनशिप के लिए 5 करोड़ रुपये के प्रारंभिक प्रावधान के साथ गतिविधियां शुरू करने को मंजूरी दी गई।

राजेश धर्माणी ने कहा कि शिमला के पास जाठिया देवी में पहले चरण में हिमुडा लगभग 21 बीघा भूमि पर 1,327 करोड़ रुपये की लागत से 919 आवासीय इकाइयों का निर्माण करेगा। इससे शिमला शहर में बढ़ती भीड़भाड़ कम होगी और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में ओलंपिक और एशियन गेम्स पदक विजेताओं, वीरता पुरस्कार विजेताओं और चिल्ड्रन ब्रेवरी अवॉर्ड प्राप्त करने वालों के लिए आवासीय प्लॉट और फ्लैट में विशेष कोटा रखने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बिलासपुर जिले के घुमारवीं में लगभग 7.69 करोड़ रुपये की लागत से 17 दुकानों, दो हॉल और एक कार्यकारी अभियंता कार्यालय सहित व्यावसायिक परिसर के निर्माण को स्वीकृति दी। कांगड़ा जिले के श्री ज्वाला जी शक्ति विहार कॉलोनी में करीब 18.61 करोड़ रुपये की लागत से 125 कनाल भूमि पर 130 प्लॉट और व्यावसायिक स्थान विकसित करने को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में अलॉटमेंट लेटर के 45 दिनों के भीतर एकमुश्त भुगतान पर 5 प्रतिशत छूट, लैंड पुलिंग पॉलिसी तथा सरकारी परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए बाय-बैक और रिडेवलपमेंट पॉलिसी को भी स्वीकृति दी गई।

किसानों और बागवानों को मौसम की सटीक जानकारी हेतु तीन डॉप्लर वेदर राडार स्थापित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों को मौसम की सटीक और समय पर जानकारी देने के लिए राज्य के तीन प्रमुख स्थानों पर डॉप्लर वेदर राडार स्थापित किए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी को संसद में दी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि शिमला जिले के कुफरी, चंबा जिले के जोत और मंडी जिले के मुरारी देवी में लगाए गए डॉप्लर वेदर राडार आधुनिक ग्राउंड आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक से काम करते हैं। ये राडार बादलों की गति, दिशा और तीव्रता का अध्ययन कर बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की स्थिति की रियल टाइम जानकारी देते हैं, जिससे किसानों और बागवानों को समय रहते सतर्क किया जा सके।

उन्होंने कहा कि आंधी, तूफान, चक्रवात और खराब मौसम की जानकारी पहले से देने के लिए मंत्रालय ने मिशन मौसम शुरू किया है, ताकि खराब मौसम से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में कुल 47 डॉप्लर वेदर राडार कार्यरत हैं।

मंत्री ने बताया कि मौसम से जुड़ी चेतावनियां मोबाइल के माध्यम से भी जारी की जाती हैं और राज्यों के साथ साझा की जाती हैं, ताकि आम लोगों तक सही समय पर सूचना पहुंच सके। भारत मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सी-डॉट के सहयोग से भारी बारिश, बर्फबारी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और आंधी-तूफान जैसी स्थितियों की पूर्व चेतावनी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को दी जाती है, जिससे जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके।

शिक्षा मंत्री ने की जुब्बल-कोटखाई में विकास एवं अवसंरचना कार्यों की समीक्षा

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जिला शिमला के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास और अवसंरचना कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल आपूर्ति, सिंचाई, सीवरेज, सड़कों और अन्य सार्वजनिक कार्यों की स्थिति का जायजा लिया।

बैठक में बताया गया कि जल शक्ति विभाग के तहत क्षेत्र में करीब 250 करोड़ रुपये की 94 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जबकि 152 करोड़ रुपये की 20 नई योजनाएं स्वीकृति के अंतिम चरण में हैं। शिक्षा मंत्री ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के तहत चल रही पब्बर लिफ्ट पेयजल योजना की प्रगति की भी समीक्षा की, जिससे 27 पंचायतों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने योजना-वार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित कार्यों की बाधाएं दूर कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंचना चाहिए। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला और कांगड़ा जिला के विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर

विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और डेटा स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में भी लगातार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां दूध और प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं, जौ, मक्की और हल्दी पर सबसे अधिक समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। इससे किसानों और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। एक राष्ट्रीय सर्वे में राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में 21वें स्थान से सीधे पांचवें स्थान पर पहुंच गया है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। चमियाणा और टांडा मेडिकल क लेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में यह सुविधा सभी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज अपने ही प्रदेश में मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निवेशकों के हित में कई सुधार किए हैं। इसी का परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश 'बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2024' में टॉप एचीवर राज्य बना है।

उन्होंने बताया कि सरकारी कामकाज को डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है और नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में हिमाचल को 'पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है, जो प्रदेश की सही नीतियों और जनभागीदारी को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं जल्द योजना विभाग को भेजें, ताकि उन्हें वर्ष 2026-27 के बजट में शामिल किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विधायकों से सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

रोहडू क्षेत्र के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने सेब की रिकॉर्ड खरीद और दूध के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने सीमा कॉलेज में बीएड की पढ़ाई शुरू करने और पेयजल योजनाओं को जल्द पूरा करने की मांग रखी।

शिमला शहरी क्षेत्र के विधायक हरीश जनारथा ने शहर की सड़कों की मरम्मत, नई संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए अलग बजट देने, पानी की योजनाओं में तेजी लाने और अंडरग्राउंड डक्ट के काम को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया।

नूरपुर क्षेत्र के विधायक रणबीर निक्का ने मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का निर्माण पूरा करने और सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के खाली पद भरने की मांग की। उन्होंने अवैध खनन रोकने के लिए पंजाब से लगती सीमा की निशानदेही करवाने की बात कही।

इंदौरा क्षेत्र के विधायक मलेंद्र राजन ने बरसात में आई बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए प्रभावित लोगों को जल्द मुआवजा देने और बाढ़ रोकने के लिए सुरक्षात्मक कार्य करने की मांग की। साथ ही गन्ना किसानों के लिए शुगर पॉलिसी बनाने और शुगर मिल स्थापित करने का आग्रह किया।

जसवां-परागपुर के विधायक बिक्रम सिंह ने सड़क परियोजनाओं को सीआरआईएफ में शामिल करने, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय भवन का निर्माण तेज करने और औद्योगिक क्षेत्र में बिजली व्यवस्था सुधारने की बात रखी।

ज्वालामुखी क्षेत्र के विधायक संजय रतन ने हेलीपोर्ट निर्माण, आईटीआई या पॉलिटेक्निक खोलने, अस्पताल सुविधाएं बढ़ाने, पुलों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने और आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त धन देने की मांग की।

सुलह क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह परमार ने पुलों के निर्माण, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के भवनों के कार्य में तेजी लाने और सिंचाई कुहलों की मरम्मत का आग्रह किया।

कांगड़ा के विधायक पवन काजल ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की जरूरत बताई।

पालमपुर के विधायक आशीष बुटेल ने पर्यटन विकास के प्रयासों की सराहना की, पानी के बढ़े बिलों की समस्या उठाई और बोर्डिंग स्कूल व लाइब्रेरी के निर्माण में तेजी की मांग की।

बैजनाथ क्षेत्र के विधायक किशोरी लाल ने सड़क निर्माण में तेजी, अस्पतालों में खाली पद भरने और एचआरटीसी डिपो के लिए नई बसें उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

बैठक में राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

1 मार्च से स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि 1 मार्च से हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों

द्वारा मोबाइल फोन लाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने यह घोषणा बिलासपुर जिले के घुमारवीं में आयोजित 69वीं अंडर-19 छात्रा हैंडबॉल स्कूल प्रतियोगिता के समापन समारोह में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग बच्चों की पढ़ाई और एकाग्रता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अक्सर देखा गया है कि लंच टाइम में भी बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी विद्यार्थी के पास स्कूल में मोबाइल पाया गया तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, मोबाइल जब्त किया जाएगा और अभिभावकों को स्कूल बुलाकर समझाया जाएगा। नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की जा रही मानक प्रक्रिया के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने खेलों के महत्व पर भी जोर देते हुए कहा कि खेलों से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। उन्होंने हैंडबॉल प्रतियोगिता की विजेता हिमाचल प्रदेश टीम को 20 लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। राज्य सरकार खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाने, खेल मैदानों के निर्माण और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि प्रदेश के विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

मुख्यमंत्री ने कैथू में एचपीएससीबी की नई शाखा का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कैथू में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक एचपीएससीबी

की नई शाखा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, ताकि आम लोगों को उनके नजदीक सुलभ बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी बैंक किसानों, छोटे व्यापारियों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल देते हुए कहा कि राज्य सरकार की जमा राशि सहकारी बैंक में रखे जाने से बैंक की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी।

उन्होंने एचपीएससीबी के कार्यो की सराहना करते हुए कहा कि बैंक आधुनिक तकनीक आधारित सेवाओं के माध्यम से आम जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि कैथू शाखा स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी।

इस अवसर पर एचपीएससीबी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया।

प्रदेश पुलिस सबसे आधुनिक, तेज और भरोसेमंद पुलिस:मुख्यमंत्री

1253 नवनियुक्त कांस्टेबलों को सौंपे नियुक्ति पत्र, 800 और भर्तियां जल्द

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले

के पुलिस कॉलेज डरोह में आयोजित 'रोजगार संकल्प मेले' के दौरान 1253 नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी चयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि इस बार पुलिस भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई गई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आई थीं, जबकि वर्तमान सरकार ने परीक्षा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित कर निष्पक्षता सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार आगामी दो महीनों में 800 और कांस्टेबलों की भर्ती करेगी, जिससे हिमाचल प्रदेश पुलिस को और मजबूती मिलेगी और कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कांस्टेबलों से कहा कि वे केवल नौकरी नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा और सेवा की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई को सरकार ने जन आंदोलन बनाया है, जिसमें पुलिस की भूमिका सबसे अहम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस देश की सबसे आधुनिक, तेज और भरोसेमंद पुलिस फोर्स में शामिल है। आपातकालीन सेवा 112 में हिमाचल पुलिस का प्रतिक्रिया समय देश में सबसे बेहतर है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों की वर्दी की गुणवत्ता सुधारने और उनकी सुविधाएं बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस अवसर पर उन्होंने नशे के विरुध शपथ दिलाई और पुलिस द्वारा किए गए बचाव अभ्यासों का अवलोकन किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

गुणवत्तापूर्ण दवाओं के लिए नई आवश्यक औषधि सूची तैयार करने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने नई आवश्यक औषधि सूची एसेंशियल ड्रग्स लिस्ट तैयार करने को कहा, जिसकी समीक्षा एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाओं की खरीद सीधे निर्माता कंपनियों से की जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी, आपूर्ति में देरी रुकेगी और व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।

उन्होंने दवाओं की सैंपलिंग और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था को और मजबूत करने पर भी जोर दिया। इसके लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में समर्पित सेल स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में यह व्यवस्था शुरू होगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और दवा निर्माता कंपनियों पर गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

आरडीजी अस्थायी व्यवस्था थी, वित्तीय अनुशासन से ही स्थिरता संभव:शेखावत

शिमला/शैल। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजस्व

घाटा अनुदान (आरडीजी) की व्यवस्था मूल रूप से अस्थायी राहत के रूप में शुरू की गई थी और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए राज्यों को अपने राजस्व संसाधन बढ़ाने तथा व्यय अनुशासन अपनाने की आवश्यकता है। वह शिमला में आयोजित एक विस्तृत प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बजट 2026, भारत की आर्थिक स्थिति, हालिया अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों और हिमाचल प्रदेश से जुड़े वित्तीय मुद्दों पर अपनी बात रखी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरडीजी की शुरुआत 12वें वित्त आयोग के दौरान गंभीर वित्तीय दबाव झेल रहे राज्यों को सीमित अवधि के लिए सहारा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसे बार-बार चेतावनियों के साथ आगे बढ़ाया गया, लेकिन इसे कभी स्थायी व्यवस्था नहीं माना गया। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के दौरान कोविड जैसी असाधारण परिस्थितियों में राज्यों को फ्रंट -लोडेड और रिकॉर्ड स्तर की सहायता दी गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश को भी पूर्व की तुलना में अधिक आरडीजी प्राप्त हुई।

शेखावत ने कहा कि वित्त आयोग ने अब स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि निरंतर अनुदानों के बजाय राज्यों को संरचनात्मक सुधारों, राजस्व वृद्धि और वित्तीय अनुशासन की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि वित्तीय घाटा आय और व्यय के अंतर से जुड़ा विषय है और इसका समाधान राजनीतिक ब्यानबाजी के बजाये ठोस वित्तीय प्रबंधन से ही संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश का कर्ज-जीडीपी अनुपात 40 प्रतिशत से ऊपर पहुंचना सावधानी का संकेत है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर हिस्सेदारी (टैक्स डिवॉल्यूशन) के नए फॉर्मूले के तहत राज्यों को मिलने वाले संसाधनों में संरचनात्मक वृद्धि की है, जिससे आरडीजी में कमी के प्रभाव को काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है, बशर्ते राज्य अपने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करें।

हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा राहत के क्षेत्रों में निरंतर सहयोग कर रही है। उन्होंने बताया कि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के तहत हिमाचल को पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 50 वर्ष की अवधि का ब्याज-मुक्त दीर्घकालिक ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसे व्यवहारिक रूप से अनुदान के समान माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन, प्रसाद और चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन योजनाओं के तहत भी राज्य को सहायता दी जा रही है।

प्राकृतिक आपदाओं पर बात करते हुए शेखावत ने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ फंड में पिछले वर्षों में कई गुना वृद्धि की गई है और राज्यों को राहत के साथ-साथ आपदा-पूर्व तैयारी और निवारक उपायों पर खर्च करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने राज्य सरकारों से जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबंधन पर अधिक निवेश करने का आग्रह किया।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौतों और कृषि से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों, डेयरी, अनाज, दाल, सब्ज़ी और मसाला उत्पादकों के हितों की पूरी तरह रक्षा की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गेहूं, चावल, दालें, सामान्य सब्ज़ियां, डेयरी उत्पाद और अधिकांश फल श्रेणियों में किसी प्रकार का बाज़ार खुलापन नहीं दिया गया है। सेब के आयात को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि न्यूनतम लैंडिंग कीमत और टैक्स संरचना के कारण स्थानीय बागवानों के हित सुरक्षित हैं।

पर्यटन क्षेत्र पर बोलते हुए शेखावत ने कहा कि यह भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख विकास इंजन बन चुका है और बजट 2026 में हेरिटेज साइट्स, हॉस्पिटैलिटी, टूर गाइड प्रशिक्षण, ईको-टूरिज्म और हाई वैल्यू कृषि फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन और कृषि को मजबूत स्तंभ बनाकर बजट 2026 देश को दीर्घकालिक विकास की दिशा में आगे ले जाने वाला दस्तावेज है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में भारत ने आर्थिक निराशा से निकलकर एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था का स्वरूप हासिल किया है। उनके अनुसार, बजट 2026 निरंतरता, सुधार, आत्मनिर्भरता और सर्वसमावेशी विकास का रोडमैप प्रस्तुत करता है, जिससे हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों को लाभ मिलने की संभावना है।

विधायक निधि रोकने पर भाजपा ने जताया कड़ा विरोध

शिमला/शैल। भाजपा विधायक दल ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर विपक्षी क्षेत्रों के साथ खुला राजनीतिक भेदभाव करने का आरोप लगाते हुये राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सौंपे गये इस ज्ञापन में विधायक क्षेत्र विकास निधि, ऐच्छिक निधि तथा विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं को जानबूझकर रोके जाने का गंभीर मुद्दा उठाया गया।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक परंपराओं को कुचला जा रहा है। अक्तूबर 2025 के बाद से विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी नहीं की गई, जिससे विधायकों के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में जनता से किए गए वादों को निभाना असंभव हो गया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के बाद पुनर्वास और विकास कार्यों के लिए निधि की सबसे अधिक आवश्यकता थी, लेकिन बजट प्रावधान होने के बावजूद सरकार ने केवल आधी राशि जारी कर शेष पर रोक लगा दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि विधायकों की ऐच्छिक निधि भी रोकी जा रही है, जिससे गरीब, बीमार और आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता नहीं मिल पा रही। इससे जनप्रतिनिधियों की विश्वसनीयता को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि परंपरा के अनुसार विधायकों से विकास प्राथमिकताएं लेकर पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में दर्ज की जाती हैं, लेकिन पिछले तीन वर्षों से विपक्षी विधायकों की प्राथमिकताओं की न तो डी.पी.आर बन रही है और न ही उन्हें नाबार्ड को भेजा जा रहा है। जहां डी.पी.आर बनी भी है, वहां उसे आगे बढ़ाने के बजाय रोका जा रहा है।

उन्होंने इसे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए कहा कि सरकार विकास नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि सरकार को तुरंत विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि जारी करने तथा विपक्षी विधायकों की विकास प्राथमिकताओं पर बिना भेदभाव कारवाई के निर्देश दिए जाएं, ताकि प्रदेश में संतुलित और न्यायसंगत विकास सुनिश्चित हो सके।

इस अवसर पर भाजपा विधायक दल के अनेक विधायक उपस्थित रहे।

आर्थिक संकट पर सरकार

...पृष्ठ 1 का शेष

के एक बड़े वर्ग को पोषित करने में लगे हुये हैं। इसलिए सैकड़ो के हिसाब से अपने मित्रों को ताजपोशीयां देकर नवाज रहे हैं। इसी मकसद से सबको धनी बनाने के लिये सबके मानदेय में लाखों की बढ़ौतरीयां की गयी है। इसी कारण से विधायकों के वेतन भत्तों और पैन्शनों में बढ़ौतरीयां की गयी। अन्यथा जो मुख्यमंत्री पद संभालते ही प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे होने की चेतावनी दे वह ईमानदारी से सरकारी खजाने का ऐसा दुरुपयोग नहीं कर सकता। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विधायकों को जनता का शुभचिंतक होने के नाते मुख्यमंत्री से लेकर हाईकमान तक सबको पूरी बेबाकी से प्रदेश के हालात से अवगत करवाना होगा। अन्यथा हिमाचल प्रदेश की कार्यप्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पर भारी पड़ेगी। यह परिस्थितियां बजट सत्र और राज्यसभा में अपना प्रभाव दिखायेगी यह तय है।

आरडीजी पर भ्रम फैलाने

...पृष्ठ 1 का शेष

वैकल्पिक कृषि और नकदी फसलों से की गई, जिससे राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय सुधार हुआ और बजट संतुलन बनाए रखने में मदद मिली।

उन्होंने वर्तमान सरकार पर परोक्ष लेकिन तीखा हमला करते हुए कहा कि एक ओर सरकार आर्थिक संकट की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में चेयरमैन, सलाहकार और अन्य पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। नई गाड़ियों की खरीद, अतिरिक्त स्टाफ, सुविधाओं और भत्तों पर लगातार खर्च बढ़ रहा है, जो वित्तीय अनुशासन के पूरी तरह खिलाफ है। यदि वास्तव में स्थिति गंभीर है, तो सबसे पहले गैर-जरूरी खर्चों पर तुरन्त रोक लगनी चाहिए।

अंत में प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश का मुखिया यदि बार-बार यह कहे कि ''खजाना खाली है'', तो इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है और निवेश व विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है। आर्थिक चुनौतियों का समाधान ब्यानबाज़ी से नहीं, बल्कि ठोस नीतियों, खर्चों की ईमानदार समीक्षा, संसाधन सृजन और सख्त वित्तीय अनुशासन से ही संभव है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को मजबूत नेतृत्व और जिम्मेदार शासन की आवश्यकता है, न कि बहानों की।